Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC)

भारत एवं उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था

(भाग-2)

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: UKPM12

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC)

भारत एवं उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था

(भाग–2)

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 011-47532596, 87501 87501
टोल फ्री : **1800-121-6260**
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

UKPSC DLP विषय सूची (Contents)

9.	**राजकोषीय नीति एवं बजट व्यवस्था**	**5–59**
	9.1 बजट व्यवस्था	6
	9.2 लोक ऋण एवं लोक व्यय	14
	9.3 केंद्रीय बजट 2018-19	18
	9.4 भारत में कराधान	25
	9.5 वस्तु एवं सेवा कर	29
	9.6 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें	48
	9.7 उत्तराखंड सरकार बजट 2018-19	50
10.	**विदेशी व्यापार**	**60–82**
	10.1 विदेशी व्यापार : सामान्य परिचय	60
	10.2 विदेशी व्यापार की संरचना	62
	10.3 निर्यात संवर्द्धन	68
	10.4 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते	72
	10.5 विदेशी व्यापार नीति, 2015–20	77
11.	**भुगतान संतुलन**	**83–105**
	11.1 भुगतान संतुलन : अर्थ एवं अवधारणा	83
	11.2 भुगतान शेष प्रबंधन	90
	11.3 रुपए की परिवर्तनीयता	93
	11.4 विदेशी निवेश	96
	11.5 विदेशी पूंजी का नियमन	101
12.	**अंतर्राष्ट्रीय संगठन**	**106–147**
	12.1 संयुक्त राष्ट्र संघ	106
	12.2 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन	108
	12.3 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, अंकटाड, यूनेस्को, यू.एन.डी.पी., जी–20	115
	12.4 सार्क, ब्रिक्स, बिम्सटेक, आसियान, एपेक, शंघाई सहयोग संगठन	122
	12.5 न्यू डेवलपमेंट बैंक (ब्रिक्स बैंक), एशियाई विकास बैंक	128
	12.6 गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नाटो	130
	12.7 अन्य महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन	132

13. नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे **148–184**

13.1 अवसंरचना 148

13.2 निम्न आय वर्गीय समूह के लिये आवास 149

13.3 नगरीय क्षेत्र के मुद्दे : शहरीकरण से उपजी समस्याएँ 151

13.4 शहरी अवसंरचना: आवास, स्वच्छता और अवसंरचना विकास योजनाएँ 153

13.5 ग्रामीण अवसंरचना : आवास, स्वच्छता और अवसंरचना विकास योजनाएँ 163

13.6 ग्रामीण साख 179

14. योजनाएँ एवं विविध **185–213**

14.1 केंद्र सरकार की योजनाएँ 185

14.2 उत्तराखंड सरकार की योजनाएँ 198

14.3 विविध 204

15. उत्तराखंड के अन्य महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिदृश्य **214–227**

15.1 उत्तराखंड में पर्यटन का आर्थिक दृष्टिकोण 214

15.2 उत्तराखंड में परिवहन एवं संचार 217

15.3 उत्तराखंड में जड़ी-बूटी उद्योग 219

15.4 उत्तराखंड में सहकारिता 223

16. आर्थिक अवधारणाएँ तथा शब्दावलियाँ **228–231**

अध्याय
9

राजकोषीय नीति एवं बजट व्यवस्था (Fiscal Policy and Budget System)

अर्थशास्त्री कींस की पुस्तक **द जनरल थ्योरी ऑफ इंप्लॉयमेंट एंड मनी** में प्रतिपादित विचारों में एक विचार यह भी है कि सरकार को राजकोषीय नीति का प्रयोग निर्गत और रोज़गार को स्थिर करने के लिये किया जाना चाहिये। कींस के अनुसार सरकार को करों तथा व्यय में परिवर्तनों के माध्यम से राजकोषीय नीति द्वारा अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास करना चाहिये।

राजकोषीय नीति : अर्थ *(Fiscal policy : Meaning)*

सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, करारोपण, बजट घाटे, सब्सिडी और हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित नीतियाँ 'राजकोषीय नीति' कहलाती हैं। करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति के प्रमुख घटक होते हैं। सरकार राजकोषीय नीति के द्वारा निजी क्षेत्रों के लिये संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों का आवंटन तथा आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका इत्यादि को प्रभावित करती है। इस नीति का संचालन सरकार वित्त मंत्रालय की सहायता से स्वयं करती है। राजकोषीय नीति के तहत अत्यधिक मुद्रास्फीति की स्थिति में कम-से-कम घाटे का बजट बनाने तथा कम-से-कम हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लेने की नीति अपनाई जाती है, साथ-ही-साथ आवश्यक वस्तुओं से कर को कम या समाप्त कर दिया जाता है। सब्सिडी को भी बढ़ा दिया जाता है, ताकि आधारभूत वस्तुओं तक आम जनता की पहुँच भी हो सके।

जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एवं व्यय की कमी के कारण मंदी जैसी स्थिति हो तब सरकार राजकोषीय नीति की सहायता से करों में कमी तथा सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि के द्वारा समग्र मांग एवं व्यय को बढ़ाने का प्रयास करके मंदी से निकलने की कोशिश करती है। इसके विपरीत जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एवं व्यय की अधिकता के कारण अभिवृद्धि की स्थिति हो तो सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से सार्वजनिक व्ययों में कमी करके तथा करारोपण में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को संतुलित करने का प्रयास करती है।

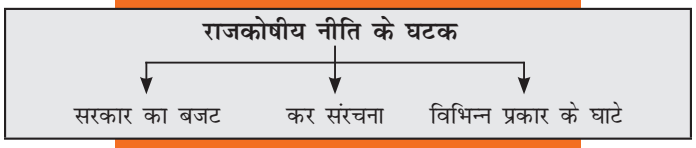

भारत की राजकोषीय नीति *(Fiscal policy of India)*

भारत की राजकोषीय नीति के वृहद् उद्देश्यों के अंतर्गत संतुलित एवं तीव्र विकास, कल्याणकारी राज्य की स्थापना और समाजवादी ढंग के समाज की रचना करना इत्यादि शामिल हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित राजकोषीय नीतियाँ अपनाई गईं–

1. ग्रामीण आधार संरचना पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि करना ताकि कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाया जा सके।
2. पूर्ण रोज़गार की स्थिति प्राप्त करने के लिये प्रयास करना।
3. सार्वजनिक क्षेत्र की घाटे में चल रही इकाइयों में विनिवेश की प्रक्रिया जारी रखना।
4. राजकोषीय घाटे को निकट भविष्य में यथासंभव शून्य करना।
5. राजकोषीय घाटे को संघ और राज्य के लिये क्रमशः 3% और 2% से कम करना।
6. महत्त्वहीन वस्तुओं (Non Merit Goods) पर दी जा रही सब्सिडी को कम करना एवं वैसी छिपी हुई सब्सिडी भी घटाना जो समर्थ लोगों को अधिक लाभ पहुँचा रही है।
7. भुगतान संतुलन की स्थिति प्राप्त करने के लिये प्रयास करना।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- भारत में बजट का राजस्व अनुमान वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है।
- सरकार के खज़ाने में कर जमा करने का दायित्व जिसके ऊपर है उसे करापात/कराघात कहते हैं।
- राजकोषीय नीति का निर्धारण केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय करता है जबकि मौद्रिक नीति आर.बी.आई. द्वारा निर्धारित की जाती है।
- बजट के हिसाब-किताब की जाँच भारतीय संसद की सार्वजनिक लेखा समिति द्वारा की जाती है।
- मूल्य संवर्द्धन कर इनवॉयस विधि के प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- केंद्र सरकार के संपूर्ण व्यय प्रारूप की समीक्षा हेतु व्यय सुधार आयोग का गठन 28 फरवरी, 2000 को किया गया।
- भारत की संचित निधि से होने वाला व्यय और भारित व्ययों के लिये संसदीय मंज़ूरी विनियोग विधेयक के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- राजकोषीय घाटे की गणना में केवल 91 दिन की परिपक्वता वाली सरकारी हुंडियों (Treasury Bill) को ही सम्मिलित किया जाता है।
- उत्तराखंड राज्य की आय के प्रमुख स्रोत कृषि, पर्वतीय वन संसाधन, पर्यटन, तीर्थाटन, औद्यानिकी, फल एवं दुग्ध उत्पादन है।
- भारत सरकार द्वारा भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर देश में ही उगाहे गए ऋण आंतरिक ऋण कहलाते हैं।
- जी.एस.टी. लागू करने के लिये 122वें संशोधन विधेयक, 2014 द्वारा संविधान में 101वाँ संशोधन 2016 किया गया तथा संविधान में नए अनुच्छेद-246(ए), 269(ए) और 279(ए) की व्यवस्था की गई है।
- ऐसी वस्तुएँ तथा सेवाएँ जिनमें एक व्यक्ति के उपभोग में कमी किये बिना दूसरे व्यक्ति के उपभोग में वृद्धि की जा सके। इनके उपभोग से कोई व्यक्ति इसलिये वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उनकी कीमत चुकता नहीं कर सकता ऐसी वस्तुएँ शुद्ध सार्वजनिक वस्तुएँ कहलाती हैं।
- शुद्ध निजी वस्तुएँ ऐसी वस्तुएँ एवं सेवाएँ हैं जिनमें एक व्यक्ति के उपभोग में कमी करने पर दूसरे व्यक्ति के उपभोग में वृद्धि हो क्योंकि वह व्यक्ति उनकी कीमत चुकता कर सकता है।
- प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा को वर्ष 2011–12 के केंद्रीय बजट से शुरू किया गया था।
- वर्ष 2012–13 के बजट में प्रभावी राजस्व घाटे को एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया।
- सक्षम परियोजना से वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।
- इसके अलावा व्यापार में सुगमता के लिये भारतीय सीमा शुल्क एकल खिड़की इंटरफेस (स्विफ्ट) का विस्तार और डिजिटल इंडिया के तहत अन्य करदाता अनुकूल पहलों और कारोबार सुगमता में भी मदद मिलेगी।
- जी.एस.टी. के लागू होने से सी.बी.ई.सी. के तहत विभिन्न अप्रत्यक्ष कानूनों में सभी करदाताओं-आयातकों-निर्यातकों-डीलरों की संख्या बढ़कर 65 लाख हो जाएगी जो फिलहाल 36 लाख है।
- पंजीकरण, भुगतान, सी.बी.ई.सी. को भेजे जाने वाले रिटर्न डेओ की प्रोसेसिंग के आई.टी. ढाँचे का वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) से एकीकरण ज़रूरी है। इसके अलावा 'सक्षम' अन्य मॉड्यूल, मसलन-ऑडिट, अपील तथा जाँच में भी प्रमुख भूमिका निभाएगा।
- 14वें वित्त आयोग ने प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा को समाप्त करने की संस्तुति की है क्योंकि यह अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार से मेल नहीं खाती।
- प्राथमिक घाटे का सर्वप्रथम वर्ष 1994–95 के बजट में प्रयोग करने वाले व्यक्ति वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह थे।
- राजस्व तथा प्राथमिक घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटे का आकार सबसे बड़ा है। सरकारी बजट घाटे की स्पष्ट तस्वीर राजकोषीय घाटा प्रस्तुत करता है।
- बिक्री कर वह कर है जो वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री पर लगता है, यह अधिवासी निकाय को चुकाया जाता है। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे केंद्रशासित राज्यों पर यह कर लागू नहीं है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. उत्तराखंड राज्य के वर्ष 2016-17 के बजट में निम्नलिखित मदों में से किसको अधिक धनराशि आवंटित की गई है?

UKPSC (Pre) 2016

(a) स्कूली शिक्षा (b) कृषि विकास
(c) औद्योगिक विकास (d) सड़क निर्माण

2. चौदहवें वित्त आयोग के अनुसार, शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने वाले मात्रा का प्रतिशत है:

UKPSC (Pre) 2016

(a) 32 प्रतिशत (b) 35 प्रतिशत
(c) 40 प्रतिशत (d) 42 प्रतिशत

3. बजट 2016-17 में भारत का वित्तीय घाटा कितना अनुमानित है? **UKPSC (Lower) Pre 2016**

(a) 2.1% (b) 3.5%
(c) 3.5% (d) 4.8%

4. 'वैट' लगता है **UKPSC (RO/ARO) Pre 2016**

(a) सीधे उपभोक्ता पर
(b) उत्पादन के पहले चरण पर
(c) उत्पादन एवं विक्रय के मध्य सभी चरणों पर
(d) उत्पादन के अंतिम चरण पर

5. 'बजट' का मुख्य उद्देश्य होता है-

UKPSC (RO/ARO) Pre 2016

(a) जवाबदेही सुनिश्चित करना
(b) प्रबन्धन के साधन के रूप में कार्य करना
(c) आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना
(d) उपर्युक्त सभी

6. चौदहवें वित्त आयोग (2015-20) ने भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की-

UKPSC (RO/ARO) Mains 2016

(a) दिसंबर, 2014 (b) जनवरी, 2015
(c) अक्टूबर, 2016 (d) मई, 2017

7. निम्नलिखित में से कौन-सा कर भारत में केंद्र सरकार द्वारा नहीं आरोपित किया जाता है?

UKPSC (ARO) Pre 2016

(a) सेवा कर (b) निगम कर
(c) मनोरंजन कर (d) आयकर

8. कर आधार में वृद्धि के साथ जब कर की दर घटती जाती है तब ये कर कहलाते हैं

UKPSC (ARO) 2016

(a) प्रगतिशील कर (b) प्रतिगामी कर
(c) आनुपातिक कर (d) अधोगामी कर

9. राजकोषीय नीति का प्रमुख अंग है:

UKPSC (आबकारी विभाग) Pre 2016

(a) उत्पादन नीति (b) कर नीति
(c) मुद्रा नीति (d) ब्याज-दर नीति

10. निम्नलिखित में से कौन गैर-योजनागत राजस्व व्यय की सूची का सबसे महत्त्वपूर्ण पद है?

UKPSC (Group B Screening) 2015

(a) रक्षा
(b) ब्याज-भुगतान
(c) खाद-अनुदान
(d) सार्वजनिक उद्यमों को ऋण

11. निम्नलिखित में से कौन सा संविधान जी.एस.टी. से संबंधित है? **UKPSC (Civil Judge) 2015**

(a) 97वाँ (b) 98वाँ
(c) 100वाँ (d) 101वाँ

12. भारत में सर्वप्रथम सेवा कर कब लगाया गया?

UKPSC (Group C) 2015

(a) 1990-91 (b) 1994-95
(c) 1996-97 (d) 1999-2000

13. सरकार का वित्तीय वर्ष शुरू होता है-

(a) कैलेंडर वर्ष से (b) आश्विन शुक्ल से
(c) अप्रैल की शुरुआत से (d) कार्तिक-शक से

14. राजकोषीय नीति का स्वर्णिम नियम है कि सरकारें उपरिचक्रीय उधार प्रत्याशा करें वित्तीय हेतु

UKPSC (FRO) 2015

(a) चालू व्यय के
(b) पुराने कर्ज के
(c) निवेश के
(d) आयातित उपभोक्ता वस्तुओं के

15. यदि कर का कराधान एवं करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे कहते हैं– **UKPSC (AE) Pre 2013**
(a) प्रत्यक्ष कर (b) परोक्ष कर
(c) प्रगतिशील कर (d) प्रतिगामी कर

16. निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने, 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिये, राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया? **UKPSC (Pre) 2012**
(a) प्रो. कीन्स (b) प्रो. पीगू
(c) प्रो. मार्शल (d) प्रो. क्राउथर

17. निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? **UKPSC (Pre) 2012**
(a) उत्पाददन नीति (b) कर नीति
(c) विदेश नीति (d) ब्याज दर नीति

18. 'वस्तु एवं सेवा कर' एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे–
(a) विजय केलकर
(b) मोंटेक सिंह अहलूवालिया
(c) अरुण जेटली
(d) नरसिम्हा

19. भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान है–
(a) राजस्व घाटा (b) आय-व्यय घाटा
(c) राजकोषीय घाटा (d) प्राथमिक घाटा

21. संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया?
(a) 1991 (b) 1976
(c) 1957 (d) 1948

21. किस राज्य/केंद्रशासित क्षेत्र में बिक्री कर लागू नहीं है?
(a) अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप
(b) पांडिचेरी
(c) गोवा, अरुणाचल प्रदेश
(d) सभी राज्य एवं केंद्रशासित क्षेत्रों में बिक्री कर लागू है।

22. भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है?
(a) वित्त मंत्रालय
(b) वित्त आयोग
(c) योजना आयोग
(d) आर.बी.आई.

23. सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है–
(a) वित्त मंत्रालय (b) योजना आयोग
(c) भारतीय रिज़र्व बैंक (d) वित्त आयोग

24. भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे कम योगदान है?
(a) राजस्व घाटा (b) आय-व्यय घाटा
(c) राजकोषीय घाटा (d) प्राथमिक घाटा

25. बजट एक लेख-पत्र है–
(a) सरकार की मौद्रिक नीति का
(b) सरकार की वाणिज्य नीति का
(c) सरकार की राजकोषीय नीति का
(d) सरकार की मुद्रा बचत नीति का

26. भारत में केंद्र सरकार की कर आय में मुख्यत: दो सबसे बड़े स्रोत हैं–
(a) केंद्रीय उत्पाद कर और निगम कर
(b) तट कर और आयकर
(c) तट कर और निगम कर
(d) निगम कर एवं आयकर

27. यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह किसके बराबर होगा?
(a) बजट घाटे के
(b) राजकोषीय घाटे के
(c) घाटे की वित्त व्यवस्था के
(d) आगामी घाटे के

28. निम्नलिखित में से कौन-सा आंतरिक ऋण का घटक है?
(1) बाज़ार ऋणदान
(2) ट्रेजरी बिल्स
(3) भारतीय रिज़र्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूति
कूट:
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 (d) 1, 2 और 3

29. निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक आय का स्रोत नहीं है?
(a) आयकर
(b) सार्वजनिक ऋण
(c) वैट
(d) अर्थसहायिकी परिदान

30. एडहॉक ट्रेजरी बिल का स्थान निम्नलिखित में से किसने लिया है?
(a) अर्थोपाय अग्रिम (b) वाणिज्यिक पत्र
(c) जमा प्रमाण पत्र (d) विनिमय विपत्र

उत्तरमाला

1. (a)	2. (d)	3. (c)	4. (a)	5. (d)	6. (a)	7. (c)	8. (b)	9. (a)	10. (b)
11. (d)	12. (b)	13. (c)	14. (a)	15. (a)	16. (a)	17. (b)	18. (a)	19. (c)	20. (c)
21. (a)	22. (a)	23. (a)	24. (d)	25. (c)	26. (d)	27. (b)	28. (d)	29. (d)	30. (a)

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 20 शब्दों में दीजिये)

(a) उत्तराखंड राज्य के प्रमुख कर-स्रोत क्या हैं? किस कर से सर्वाधिक आय प्राप्त होती है?
UKPSC (Mains) 2016

(b) वित्तीय घाटे तथा आय घाटे में अंतर कीजिये।
UKPSC (Mains) 2016

(c) केंद्र सरकार के आय के दो स्रोत लिखिये।
UKPSC (Mains) 2012

(d) 'चौदहवें वित्त आयोग' के अध्यक्ष के बारे में विवेचना कीजिये। **UKPSC (Mains) 2012**

(e) राजस्व घाटा किस प्रकार निश्चित होता है?

(f) मूल्य वृद्धि कर किस प्रकार लगाया जाता है?

(g) केंद्र सरकार अपने बजट में सामाजिक क्षेत्र के किन मदों पर सामान्यतया व्यय करती है?

(h) जेंडर बेस बजट को समझाइये।

(i) लैफर वक्र क्या होता है?

(j) राजस्व घाटा तथा प्राथमिक घाटा को परिभाषित करें।

(k) जी.एस.टी. प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें।

(l) प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की उदाहरण सहित व्याख्या करें।

लघु एवं दीर्घउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 50, 125 या 250 शब्दों में दीजिये)

1. अप्रत्यक्ष कर क्या है? उदाहरण दीजिये।
(50 शब्द) UKPSC (Mains) 2016

2. वस्तु एवं सेवा कर की पाँच विशेषताएँ लिखिये।
(125 शब्द) UKPSC (Mains) 2016

3. मूल्य वर्द्धित कर (वैट) की व्याख्या कीजिये।
(50 शब्द) UKPSC (Mains) 2012

4. करारोपण के समान सिद्धांत एवं उत्पादकता सिद्धांत को समझाइये। **(125 शब्द) UKPSC (Mains) 2012**

5. सरकार की आर्थिक नीति के उपकरणों के रूप में राजकोषीय नीति एवं मौद्रिक नीति एक-दूसरे की पूरक होती है। इस कथन को समझाइये।
(250 शब्द) UKPSC (Mains) 2012

6. हरित अधिलाभ क्या है?
(50 शब्द) UKPSC (Mains) 2012

7. 'ग्रीन बोनस' क्या है? उत्तराखंड का इस पर दावा कितना मजबूत है? **(125 शब्द) UKPSC (Mains) 2012**

8. उत्तराखंड सरकार के वर्ष 2018-19 के बजट की प्रमुख विशेषताएँ लिखिये।

9. एक देश के आर्थिक विकास में जन वित्त की भूमिका क्या है?

10. भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण के प्रमुख घटक क्या-क्या हैं? इस ऋण की हाल ही में बढ़ती प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिये।

11. भारत जैसे विकासशील देश में आपके विचार में जी. एस.टी. प्रणाली कितनी सार्थक होगी? अपने तर्कों को स्पष्ट कीजिये।

12. भारत में सार्वजनिक व्यय को संसद जिन विधियों से नियंत्रित करती है, उनकी विवेचना कीजिये।

13. भारत में नई आर्थिक नीति के आने के बाद किये गए कर सुधारों को अपने शब्दों में लिखें।

14. भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक ऋण की भूमिका क्या है?

अध्याय
10

विदेशी व्यापार (Foreign Trade)

वैश्वीकरण के दौर में विश्व व्यापार एक अपरिहार्य आवश्यकता है। वैश्विक व्यापार में वृद्धि होने से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निर्भरता भी निरंतर बढ़ रही है। विदेशी व्यापार का अर्थ दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार होता है। किसी भी देश के विदेशी व्यापार में उसके आयात और निर्यात दोनों घटकों को शामिल किया जाता है। कोई भी देश उत्पादन एवं उपभोग क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं होता है, इसलिये विदेशी व्यापार अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी व्यापार के बिना देश अपनी घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं तक सीमित रह जाएंगे। इसी कमी को दूर करने के लिये विदेशी व्यापार की आवश्यकता का जन्म हुआ है। विदेशी व्यापार को विश्व व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। विदेशी व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक सहयोग से एक-दूसरे पर निर्भरता तथा एक-दूसरे की भागीदारी एवं सहायता से आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है।

10.1 विदेशी व्यापार : सामान्य परिचय *(Foreign Trade : General Introduction)*

"दो राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय-विक्रय को विदेशी व्यापार कहते हैं।" किसी देश के विदेशी व्यापार से उसकी अर्थव्यवस्था की प्रकृति और उसके आकार का पता चलता है। विदेश व्यापार किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्रिया में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण द्वारा उत्पादन साधनों की दक्षता और कार्य कुशलता में वृद्धि कर आर्थिक उन्नयन करता है। खुली अर्थव्यवस्था को विदेशी व्यापार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। विदेशी व्यापार की महत्ता वैश्वीकरण के इस दौर में बहुत अधिक बढ़ गई है। किसी भी देश के लिये विदेशी व्यापार का महत्त्व निम्नलिखित रूप में है-

1. यह विदेशी मुद्रा अर्जन का प्रमुख साधन है।
2. विभिन्न देशों के मध्य पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करता है।
3. आवश्यक वस्तुओं के आयात तथा अधिशेष वस्तुओं के निर्यात से अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित होता है।
4. बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन करता है।
5. मशीनरी, तकनीक एवं पूंजीगत आयात से अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक मज़बूती आती है।
6. विदेशी व्यापार किसी भी राष्ट्र की उन्नति का महत्त्वपूर्ण कारक है।

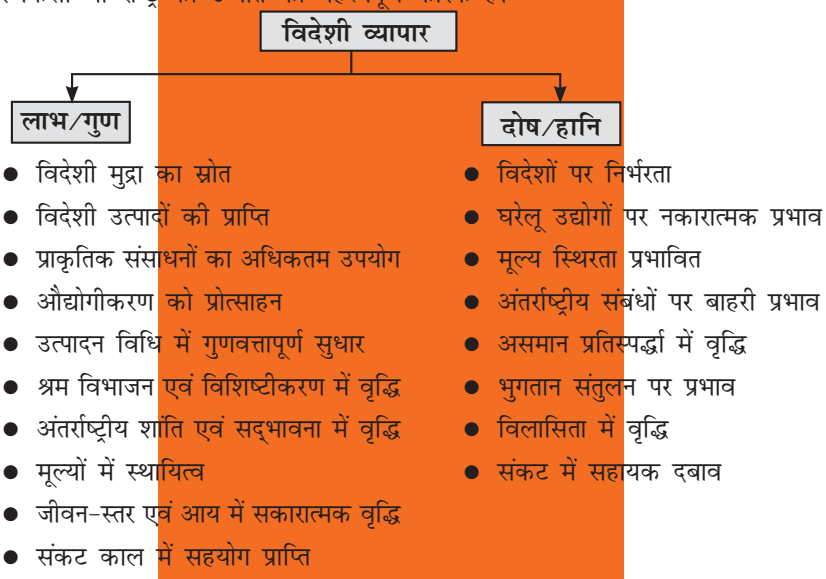

अध्याय
11

भुगतान संतुलन (Balance of Payment)

किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास एवं संवृद्धि में उस राष्ट्र के आंतरिक एवं बाह्य व्यापार का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी राष्ट्र की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आंतरिक साधनों एवं क्रियाओं के द्वारा पूर्ण नहीं की जा सकती इसलिये बाह्य या विदेशी व्यापार को अनुकूल रखे जाने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। देश की आर्थिक प्रगति के लिये निर्यात बढ़ाने एवं आयात निर्भरता कम करने का निरंतर प्रयास किया जाता है। निर्यात में वृद्धि भुगतान संतुलन एवं विदेशी विनिमय कोष के लिये भी आवश्यक है। किसी भी देश के विदेशी लेन-देन का पूर्ण विवरण भुगतान संतुलन के माध्यम से ज्ञात होता है। भुगतान संतुलन किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को चालू खाते एवं पूंजीगत खातों के माध्यम से प्रस्तुत करता है।

11.1 भुगतान संतुलन : अर्थ एवं अवधारणा *(Balance of Payment : Meaning and Concept)*

किसी देश का भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि, सामान्यत: एक वित्तीय वर्ष, में उस देश और शेष विश्व के साथ उसके सभी व्यापार, जिनके मौद्रिक मूल्य की गणना हो सकती है, का क्रमबद्ध विवरण होता है। दूसरे शब्दों में भुगतान संतुलन खाते इस प्रकार के खाते होते हैं जिनमें किसी अर्थव्यवस्था अथवा देश का शेष विश्व के साथ सभी प्रकार के मौद्रिक लेन-देन (Monetary Transactions) का लेखांकन दर्ज किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के आर्थिक लेन-देन (दृश्य, अदृश्य या पूंजीगत) का समस्त विवरण उपलब्ध होता है।

कोई देश जब विश्व के अन्य देशों को वस्तु एवं सेवाएँ विक्रय करता है तो उसे निर्यात कहते हैं तथा दूसरे देशों से जिन वस्तु एवं सेवाओं का क्रय करता है उसे हम उसका आयात कहते हैं। आयात-निर्यात के दौरान दृश्य मदों एवं अदृश्य मदों के तहत प्रविष्टि की जाती है। दृश्य मदों के अंतर्गत वस्तुओं के आदान-प्रदान तथा अदृश्य मदों के अंतर्गत सेवाओं (पर्यटन, चिकित्सा, कंसल्टेंसी, सॉफ्टवेयर, शिक्षा) के आदान-प्रदान को सम्मिलित किया जाता है। पूंजी खाते के अंतर्गत बैंकिंग जमा, विदेशी ऋण, विदेशी निवेश, आप्रवासियों और एन.आर.आई. जमा आदि को सम्मिलित किया जाता है। यह मौद्रिक लेन-देन वस्तुओं के निर्यात एवं आयात (दृश्य मदें), सेवाओं के निर्यात एवं आयात (अदृश्य मदें), वित्तीय परिसंपत्तियों, जैसे-स्टॉक्स, बॉण्ड्स के अंतर्राष्ट्रीय क्रय-विक्रय, वास्तविक परिसंपत्तियों, जैसे-प्लांट एवं मशीनरी के अंतर्राष्ट्रीय क्रय-विक्रय के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। यह लेन-देन जिस खाते में दर्ज किया जाता है, उसे ही 'भुगतान संतुलन खाता' कहते हैं। किंडलबर्गर के शब्दों में, "एक देश का भुगतान संतुलन उस देश के निवासियों तथा विदेशी देशों के निवासियों के बीच में किये गए सभी आर्थिक सौदों का क्रमबद्ध लेखा है।"

इसके दो पक्ष होते हैं- 1. क्रेडिट साइड, 2. डेबिट साइड।

- क्रेडिट साइड में उन मदों को दिखाया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा आती है, जबकि डेबिट साइड में उन मदों को दिखाया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा बाहर जाती है।
- **भुगतान संतुलन खाता में दिखाई जाने वाली मदों को दो भागों में बाँटा गया है-**

1. दृश्य मदें (Visible Items)

इसके तहत भौतिक वस्तुओं के आयात-निर्यात को भुगतान संतुलन खाते में वस्तु खाता (Goods A/c) के तहत दिखाया जाता है। सामान्य तौर पर किसी देश के आयात-निर्यात का अर्थ वस्तु खाते से लगाया जाता है अर्थात् किसी देश के आयात-निर्यात का अर्थ दृश्य मदों के आयात एवं निर्यात से होता है और इन दृश्य मदों के आयात-निर्यात का अंतर 'व्यापार संतुलन' (Balance of Trade) कहलाता है।

अध्याय
12

अंतर्राष्ट्रीय संगठन (International Organisation)

'अंतर्राष्ट्रीय संगठन' पद का प्रयोग सर्वप्रथम स्कॉटलैंड के प्रमुख विधिवेत्ता जेम्स लोरिमर ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन संस्थाओं को कहते हैं जिनके सदस्य, कार्यक्षेत्र, प्रकृति, भूमिका एवं विस्तार वैश्विक स्तर पर हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आधारशिला अपने हितों की रक्षा के लिये विभिन्न राज्यों के मध्य स्वेच्छापूर्ण तरीके के स्वीकार्य अनुशासन एवं नियंत्रण की आवश्यकता ने रखी। विभिन्न देशों द्वारा अपनी समस्याओं तथा अन्य वैश्विक विवादों पर साझा विचार-विमर्श के माध्यम से सहमति एवं समाधान प्राप्त करने तथा पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निष्पक्ष एवं तटस्थ मंच की स्थापना की आवश्यकता ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जन्म दिया। ये संगठन विभिन्न राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा करते हुए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, सहयोग एवं स्पर्द्धा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कई प्रकार की श्रेणियों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्यरत हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं सहयोग के लिये संयुक्त राष्ट्र संगठन की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

इसी संदर्भ में देखें तो, वैश्विक स्तर पर पूंजी एवं तकनीकी के लेन-देन के माध्यम से संतुलित एवं समन्वित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर व्यापार एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिये मुक्त व्यापार समझौतों के क्रियान्वयन से आसियान, सार्क, शंघाई सहयोग संगठन, एपेक, यूरोपीय यूनियन आदि जैसे संगठन भी महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

12.1 संयुक्त राष्ट्र संघ *(United Nations)*

क्या यह एक विचित्र संयोग है कि मानव आचरण में युद्ध एवं शांति, विध्वंस एवं निर्माण के बीज एक साथ निहित दिखाई देते हैं जैसा कि नेपोलियन युद्धों के बाद होली एलायंस, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् राष्ट्र संघ की स्थापना एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसके प्रमाण के रूप में दिखाई देते हैं।

प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् राष्ट्र संघ की स्थापना में जहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति **वुडरो विल्सन** ने प्रमुख भूमिका निभाई थी वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैसी ही भूमिका एक अन्य अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी. रूजवेल्ट की थी।

संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर करने के साथ हुई। दो विश्व युद्धों की विभीषिका एवं राष्ट्र संघ की असफलता के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं सहयोग की आवश्यकता ने संयुक्त राष्ट्र संघ को जन्म दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क (संयुक्त राज्य अमेरिका) में है और इसके वर्तमान सदस्यों की संख्या 193 है। 24 अक्टूबर को हर वर्ष 'संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस' के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस (पुर्तगाल) हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य *(Objectives of United Nations)*

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 के अनुसार इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं-

- अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना।
- समान अधिकार और लोगों को आत्म-निर्णय सिद्धांत के आधार पर देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना।
- अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय समस्याओं के समाधान के लिये सहयोग करना और मानवाधिकारों एवं बुनियादी स्वतंत्रता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना।
- इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रयास कर रहे देशों की गतिविधि में समन्वय स्थापित करने के लिये एक केंद्र के रूप में कार्य करना।

समय के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन उद्देश्यों से जुड़े हुए लक्ष्य भी निर्धारित किये हैं, ये हैं- निरस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना।

अध्याय
13

नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे (Issues of Urban and Rural Areas)

"आदर्श समाज गतिशील होना चाहिये, उसमें एक भाग में हो रहे परिवर्तन को दूसरे भाग तक पहुँचाने के भरपूर माध्यम होने चाहियें।"

–डॉ. बी.आर. अंबेडकर

विकास परिवर्तन की एक ऐसी सतत् प्रक्रिया है, जो लोगों को इस योग्य बनाती है कि वे सक्षम एवं सृजनात्मक बन सकें। विकास सकारात्मक परिवर्तन को इंगित करता है। पिछड़ेपन के साथ मानव विकास संभव नहीं है इसलिये विकास योजनाएँ मानव विकास तथा उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त करने के लिये लक्ष्य करके बनाई जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम की ओर से प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें जीवन-स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समानता आदि मानकों को विकास का प्रमुख वाहक माना जाता है। विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयास करती है। इस रूप में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार नीति का प्रतिपादन किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को आगे बढ़ाने में नगरीय एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों की महत्त्वपूर्ण एवं समान भूमिका है। चूँकि विकास का प्रमुख वाहक आधारभूत संरचना को माना जाता है इसलिये आधारभूत संरचना या अवसंरचना के विकास पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। अवसंरचना विकास समावेशी विकास, आर्थिक संवृद्धि, निर्धनता कम करने तथा वृहत् विकास लक्ष्यों को पाने के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण है।

13.1 अवसंरचना *(Infrastructure)*

किसी भी अर्थव्यवस्था के सुचारु रूप से कार्य करने, विकास करने एवं प्रगति के लिये जिन सुविधाओं, क्रियाओं व सेवाओं की आवश्यकता होती है, उसे अवसंरचना, अधोसंरचना या आधारभूत संरचना कहा जाता है। अवसंरचना आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के मूल तत्त्व को प्रकट करती है तथा सहयोगी व्यवस्था का कार्य करती है, जैसे-सड़क, बिजली, परिवहन, संचार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था, ऊर्जा आदि।

अवसंरचना या आधारभूत संरचना को दो भागों में विभाजित किया जाता है-

(1) *आर्थिक अवसंरचना (Economic Infrastructure)*

इसके अंतर्गत उन सभी तत्त्वों को सम्मिलित किया जाता है जो आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ हैं एवं उनकी वृद्धि में सहायक होते हैं। आर्थिक विकास की बुनियादी आवश्यकता के घटकों को आर्थिक अवसंरचना कहा जाता है। इसमें शक्ति, परिवहन, दूरसंचार आदि को सम्मिलित किया जाता है।

(2) *सामाजिक अवसंरचना (Social Infrastructure)*

इसके अंतर्गत उन सभी तत्त्वों को सम्मिलित किया जाता है जो सामाजिक गतिविधियों के विस्तार एवं विकास में सहायक हैं तथा सहयोगी भूमिका निभाते हैं। ये मानव संसाधन विकास और मानव पूंजी निर्माण में सहायक हैं। समाज को कुशल, निपुण एवं स्वस्थ मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली अवसंरचना को सामाजिक अवसंरचना कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि को शामिल किया जाता है।

अवसंरचना की भूमिका *(Role of infrastructure)*

देश के आर्थिक विकास एवं प्रगति में अवसंरचना की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचनाएँ एक-दूसरे की पूरक हैं। सामाजिक अवसंरचनात्मक ढाँचे के बिना आर्थिक अवसंरचनात्मक ढाँचे का कोई अर्थ नहीं है तथा आर्थिक अवसंरचनात्मक ढाँचे के बिना सामाजिक अवसंरचनात्मक ढाँचा औचित्यहीन है। इसलिये सामाजिक एवं आर्थिक अवसंरचना का संयुक्त विकास आवश्यक है। ये निम्नलिखित भूमिका निभाती हैं-

अध्याय
14

योजनाएँ एवं विविध (Schemes and Miscellaneous)

एक कल्याणकारी राष्ट्र में गरीबों एवं वंचित वर्गों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलाई जाती हैं। योजनाओं के माध्यम से सरकार आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय एवं आर्थिक संवृद्धि सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। इसी संदर्भ में केंद्र एवं उत्तराखंड सरकार की कुछ महत्त्वपूर्ण योजनाओं का वर्णन यहाँ किया जा रहा है।

14.1 केंद्र सरकार की योजनाएँ *(Central Government's Schemes)*

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना *(Pradhanmantri Fasal Bima Yojana)*

- इस योजना को 13 जनवरी, 2016 को मंजूरी प्रदान की गई।
- यह योजना वर्ष 2016 के खरीफ सत्र से लागू है।
- प्राकृतिक आपदा (चक्रवात, ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा, तूफान इत्यादि), कीटों एवं बीमारियों का प्रकोप व मौसमी गतिविधियों के कारण प्रभावित फसल, बुआई व कटाई के पश्चात् होने वाले नुकसान को इस श्रेणी में रखा गया है।
- किसानों को कृषि क्षेत्र में नवाचार एवं आधुनिक पद्धति को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है।
- किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिये केवल 2% तथा रबी फसल के लिये 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिये प्रीमियम 5% निर्धारित किया गया है।
- भारत सरकार द्वारा 2018–19 के बजट में प्रस्तुत योजना के लिये 13000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

कृषि डाक प्रसार सेवा *(Krishi Dak Prasar Seva)*

- यह केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों तक बीज पहुँचाने के लिये भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित सेवा है, जिसके तहत चिह्नित किसानों तक आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा उन्नत बीज पहुँचाए जा रहे हैं।
- खेती की उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य है चिह्नित गाँवों के किसानों तक आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा उन्नत बीजों को डाक के माध्यम से पहुँचाना।
- वर्तमान में यह योजना देश के 14 राज्यों के 100 ज़िलों में शुरू की गई है। इसे कृषि विज्ञान केंद्रों एवं डाकघरों के माध्यम से संचालित किया जाता है।

किसान कॉल सेंटर *(Kisan Call Center)*

- कृषि में आई.सी.टी. (Information and communication technology) को ध्यान में रखकर कृषि मंत्रालय द्वारा 21 जनवरी, 2004 को किसान कॉल सेंटर योजना को प्रारंभ किया गया था। ये कॉल सेंटर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के 14 विभिन्न स्थानों में कार्यरत हैं। इसके लिये देशव्यापी 11 अंकों वाली एक टोल फ्री नंबर-18001801551 जारी किया गया।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं का समाधान स्थानीय भाषा में किसानों को मोबाइल फोन के माध्यम से उपलब्ध कराना है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन *(Rashtriya Gokul Mission)*

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 28 जुलाई, 2014 को देशी गायों के संरक्षण तथा उनकी नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित करने के लिये राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई।

अध्याय
15

उत्तराखंड के अन्य महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिदृश्य (Other Significant Economic Scenarios of Uttarakhand)

उत्तराखंड अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति, हिमालयी जलवायु, नैसर्गिक, प्राकृतिक दृश्यों एवं संसाधनों की प्रचुरता के कारण देश में प्रमुख स्थान रखता है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ प्रसिद्ध मंदिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमनोत्री आदि चारधाम भी स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ सिक्खों का तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब भी विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। उत्तराखंड जैव विविधता के साथ ही 175 दुर्लभ प्रजाति के सुगंधित और औषधीय पौधों से भी समृद्ध है। यहाँ पर लगभग सभी जलवायु क्षेत्र हैं, जिस कारण यह बागवानी, फूलों की खेती और कृषि जैसे अनेक व्यावसायिक फसलों के लिये उपयुक्त अवसर है। साहसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, प्राकृतिक एवं स्वास्थ्य दृष्टि से पर्यटन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन भी यहाँ आर्थिक संसाधन हैं, अपने अस्तित्व में आने की अल्पावधि के बावजूद उत्तराखंड विनिर्माण उद्योग, पर्यटन और बुनियादी ढाँचे में निवेश के लिये एक महत्त्वपूर्ण गंतव्य के रूप में उभरा है। राज्य की भौगोलिक रूप रेखा के अनुसार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को उनकी पूर्ण क्षमता के साथ विकसित करने के लिये उत्तराखंड सरकार नीतिगत उपाय कर रही हैं।

15.1 उत्तराखंड में पर्यटन का आर्थिक दृष्टिकोण *(Economic Approach to Tourism in Uttarakhand)*

हिमालय के नयाभिराम अलौकिक सौंदर्य एवं शीतलता से अभिभूत, "देवभूमि" उत्तराखंड अनादिकाल से ही देश-विदेश के पर्यटकों/यात्रियों को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित करता आ रहा है। विश्व प्रसिद्ध चारधाम श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री-यमुनोत्री तथा हेमकुण्ड-लोकपाल, नानकमत्ता, मीठा-रीठा साहिब एवं पिरान कलियर नामक विभिन्न धर्मों के पवित्र तीर्थ स्थलों से युक्त इस प्रदेश में पर्यटन की प्रमुख विधा, तीर्थाटन, प्राचीन काल से ही प्रभावी रही है।

उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा रमणीय पहाड़ी राज्य है। उत्तर भारत के लगभग सभी प्रमुख हिल स्टेशन उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। हिंदुओं की आस्था के प्रतीक चारधाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री प्रसिद्ध तीर्थस्थल हैं। प्रमुख हिल स्टेशन मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, धनौल्टी, लैंसडाउन, चोपता, वैली ऑफ फ्लॉवर और सत्तल है। हिल स्टेशन की सुरम्यता के साथ-साथ धार्मिक महत्त्व के स्थान होने के कारण वर्ष भर पर्यटकों/तीर्थयात्रियों को जमावड़ा लगा रहता है। हरे-भरे और घने जंगल वाले इस राज्य में 12 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ अभयारण्य इसे प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग बनाते हैं।

उत्तराखंड में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन उद्योग को राज्य के आर्थिक विकास हेतु सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान बनी है, क्योंकि पर्यटन को भविष्य में आर्थिक विकास के प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में वर्ष 2017-18 में पर्यटन क्षेत्र, जिसमें ट्रेड, होटल एवं रेस्टोरेंट को सम्मिलित करते हुए कुल योगदान लगभग 13.57 प्रतिशत है। प्रदेश में होने वाली समस्त प्रकार की पर्यटन गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु प्रदेश में पर्यटन विकास परिषद की स्थापना की गई है। पर्यटन के क्षेत्र में स्वरोज़गार के अवसर सुलभ कराने के साथ-साथ उत्तराखंड राज्य की आर्थिक उन्नयन की दिशा में पर्यटन अपना बहुमूल्य योगदान दे रहा है।

वर्ष 2002 से वर्ष 2017 तक उत्तराखंड में आए हुए पर्यटकों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है। किन्तु वर्ष 2011 एवं 2013 में उत्तराखंड में आए पर्यटकों की संख्या में गत वर्षों की तुलना में कमी आई है। जहाँ वर्ष 2002 में 117.08 लाख पर्यटक उत्तराखंड आए, वहीं वर्ष 2017 में यह संख्या 347.23 लाख रही। इस प्रकार वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2017 में आए पर्यटकों की संख्या में 196.57 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

अध्याय
16

आर्थिक अवधारणाएँ तथा शब्दावलियाँ (Economic Concepts and Terminology)

- **आर्बिट्रेज (Arbitrage) :** विभिन्न विदेशी मुद्राओं को एक साथ इस उद्देश्य से खरीदना और बेचना जिससे विश्व के विभिन्न बाज़ारों में विदेशी विनिमय दरों में पाए जाने वाले अंतर से लाभ उठाया जा सके, आर्बिट्रेज कहलाता है।
- **एन्युटी (Annuity) :** किसी एक पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष एक या अधिक किस्तों में होने वाला भुगतान एन्युटी कहलाता है, जैसे- सरकारी ऋणपत्रों पर ब्याज का भुगतान।
- **एडवांस डिक्लाइन (Advance decline) :** यह शेयर बाज़ार की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने वाला एक माप है। किसी समयावधि में मूल्य वृद्धि को प्रदर्शित करने वाले शेयरों की संख्या का मूल्य ह्रास वाले शेयरों की संख्या के साथ अनुपात ही एडवांस डिक्लाइन कहलाता है।
- **एयर पॉकेट (Air pocket) :** यदि किसी कंपनी के शेयरों के पहले दिन के बंद भाव तथा दूसरे दिन के खुलने वाले भाव में काफी अंतर होता है तो वह स्थिति एयर पॉकेट की होती है। यह कई कारणों से घटित होता है। जैसे कि यदि किसी कंपनी के विषय में कोई प्रतिकूल सूचना आती है तो कंपनी के शेयरों के भाव गिर जाते हैं। शेयरों के भाव में उतार-चढ़ाव की स्थिति का होना सामान्य बात है।
- **अग्रिम कर (Advance tax) :** अग्रिम कर प्रत्येक वर्ष मार्च, सितंबर एवं दिसंबर में देय होता है ताकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही आगामी वित्तीय वर्ष के बजट के संबंध में अपनी राजस्व प्राप्तियों से अवगत हो सके। अग्रिम कर अर्जित आय के आधार पर देय सिद्धांत पर आधारित है।
- **बिटकॉइन (Bitcoin) :** यह समान समूह और जान-पहचान वाले लोगों के बीच इलेक्ट्रॉनिक मनी और पेमेंट नेटवर्क का खुला माध्यम है।
- **आधार प्रभाव (Base effect) :** वर्तमान आँकड़ों की गणना पर पहले के आँकड़ों का पड़ने वाला प्रभाव 'आधार प्रभाव' कहलाता है। स्फीति दर में वृद्धि के संदर्भ में वर्तमान स्फीति दर की गणना पर विगत वर्षों की कीमतों का पड़ने वाला प्रभाव आधार प्रभाव कहलाता है।
- **बूम (Boom) :** अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं की तेज़ी से विस्तार की स्थिति को बूम कहा जाता है। यह स्थिति मंदी के विपरीत है। मांग में वृद्धि के कारण ही किसी उद्योग विशेष में बूम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- **काला बाज़ार (Black market) :** बाज़ार में जमाखोरी द्वारा वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा करके उनकी कीमतों को बढ़ाकर लाभ कमाने को काला बाज़ार कहते हैं।
- **काला धन (Black money) :** जिस धन का हिसाब-किताब अधिकारियों से छिपाकर रखा जाता है, उसे काला धन कहते हैं।
- **बुरा ऋण (Bad debt) :** वह ऋण जिसकी वसूली संभव न हो अथवा संदिग्ध हो, बुरा ऋण माना जाता है।
- **ब्रिज लोन (Bridge loan) :** कंपनियाँ प्राय: शेयर तथा डिबेंचर जारी करके पूंजी का विस्तार करती हैं। कंपनी को शेयर जारी करके पूंजी जुटाने में तीन माह या उससे भी अधिक समय लगता है। इस समयावधि में अपना कार्य जारी रखने के लिये कंपनियाँ बैंकों से आंतरिक अवधि के लिये ऋण प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रकार के ऋण को ब्रिज लोन कहते हैं।
- **ब्लू चिप (Blue chip) :** जिन कंपनियों का प्रबंध अत्यधिक कुशल तथा सुदृढ़ है, उन कंपनियों के शेयरों के लिये ब्लू चिप शब्द का प्रयोग किया जाता है। इनको बेचने तथा खरीदने में कोई कठिनाई नहीं होती।
- **ब्लू बॉक्स (Blue box) :** कृषि समझौते के अनुसार विभिन्न देश उत्पादन के उद्देश्य से कुछ सीमा तक सब्सिडी की अनुमति देते हैं, जैसे-बिजली, सिंचाई, उर्वरक आदि आगतों में दी जाने वाली सब्सिडी। इस सब्सिडी को ही ब्लू बॉक्स कहते हैं।
- **ब्लू कॉलर जॉब (Blue collar job) :** द्वितीयक क्षेत्र से संबद्ध ऐसे श्रमिकों को जो उत्पादन-प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध होते हैं, उन्हें ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS

YouTube Drishti IAS

drishtiias

drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 011-47532596, +91-8130392354, 813039235456